भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1807
जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

स्मार्ट मीटरों की स्थापना

1807. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश भर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में कई खामियां हैं और हाल के दिनों में उन्हें लगाने का कार्य बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्मार्ट मीटरों में पाई गई खराबी के कारण बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड़) सरकार द्वारा इस स्थिति में और सुधार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के साथ-साथ राज्य यूटिलिटियों द्वारा स्वयं स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए राज्यों का वित्तपोषण कर रही है। ईईएसएल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली आदि राज्यों में अपनी स्वतंत्र पहल पर डिस्कॉमों द्वारा शुरू की जा रही स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं को ओपेक्स के आधार पर भी कार्यान्वित कर रही है, जिसमें ईईएसएल प्रारंभिक पूंजीगत व्यय कर रहा है और डिस्कॉम मासिक किराया आधार पर ईईएसएल को पुनर्भुगतान कर रहे हैं। अभी तक, भारत सरकार की पूर्वोक्त स्कीमों और डिस्कॉमों की पूर्वोक्त परियोजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों में लगभग 25.71 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 30.06.2021 को अनुमोदित संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के तहत, दिसंबर, 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के आरंभिक चरण में कोई प्लग एंड प्ले समाधान उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर संस्थापित करने की परियोजना देश में अपनी तरह की सबसे पहली तथा सबसे बड़ी परियोजना थी और स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के आईटी घटकों में शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा था। परिणामस्वरूप स्मार्ट मीटर की संस्थापना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था जबकि तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खराब मीटरों के सूचित मामलों में विद्युत उपभोक्ताओं को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) "मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन" (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटी अवसंरचना की सुरक्षा लेखापरीक्षा।

(ii) एएमआई प्रणाली की यूजर एक्सेपटेंस टेस्टिंग प्रयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) 29 दिसंबर, 2020 से आयोजित की जा रही है। कुल मिलाकर, 746 परीक्षण मामलों का परीक्षण करने की योजना बनाई गई थी और सभी मामलों का परीक्षण किया जा चुका है। अगस्त, 2021 तक यूएटी पूरी होने की उम्मीद है।

(iii) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित स्मार्ट मीटरों का परीक्षण। आरम्भ में आठ समूहों में से, प्रत्येक से एक मीटर का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में तीन मीटर पास हुए। पांच समूहों में से, जिसमें नमूना मीटर मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए थे, प्रत्येक समूह से आठ मीटरों (कुल 40) का परीक्षण किया गया। सभी 40 मीटर मानदंडों के अनुरूप पाए गए। इसके बाद, 57 और मीटरों का परीक्षण किया गया है तथा ये सभी 57 मीटर मानदंडों के अनुरूप पाए गए हैं।

इस स्थिति की न केवल डिस्कॉम स्तर पर अपितु मंत्रालय स्तर पर मासिक समीक्षा में भी निगरानी की जा रही है।

****